RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 192
दि. 13.11.2025, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बोत्सवाना पहुंची; राष्ट्रपति बोको के साथ द्विपक्षीय बैठक की और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता का नेतृत्व किया

राष्ट्रपति ने कहा, भारत, बोत्सवाना के साथ सम्बंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है

राष्ट्रपति ने भारत में अपने देश से चीते भेजने पर सहमति के लिए राष्ट्रपति बोको और बोत्सवाना के लोगों को धन्यवाद दिया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु अंगोला और बोत्सवाना की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में कल (11 नवंबर, 2025) बोत्सवाना के गैबोरोन पहुंचीं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली बोत्सवाना यात्रा है। राष्ट्रपति के साथ इस राजकीय यात्रा पर जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री, श्री वी. सोमन्ना और संसद सदस्य, श्री परभुभाई नागरभाई वसावा और श्रीमती डीके अरुणा भी गए हैं।

गैबोरोन स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में आज (12 नवंबर, 2025) कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मु का बोत्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

बोत्सवाना में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति बोको ने इस बात का उल्लेख किया कि "लोकतंत्र का जनक" भारत, बोत्सवाना की विकास यात्रा में प्रेरणा और समर्थन का एक अटूट स्रोत रहा है। उन्होंने शिक्षा, लैंगिक समानता और हाशिए पर आने वाले लोगो के उत्थान को बढ़ावा देने में राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से बोत्सवाना द्वारा आयोजित यह किसी भी देश की पहली राजकीय यात्रा है, जो भारत के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों के महत्व को दशार्ती है।

व्यापक व्यक्तिगत बैठकों और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह यात्रा द्विपक्षीय सम्बंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति की पहली बोत्सवाना यात्रा है। 2026 में दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के ढांचे के अंतर्गत अफ्रीका के साथ साझेदारी का विस्तार किया जा सके। महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, बोत्सवाना के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उसके सम्बंध और प्रगाढ़ हो सकें तथा

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि बोत्सवाना 'प्रोजेक्ट चीता' के अगले चरण के तहत भारत में चीतों को फिर से बसाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण पहल है और इसका उद्देश्य भारत के इकोसिस्टम में चीतों को पुनर्स्थापित करना है। उन्होंने राष्ट्रपति बोको और बोत्सवाना के लोगों को भारत में अपने देश से चीते भेजने पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया।

दोनों नेताओं की उपस्थिति में फामाकीपिया पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे बोत्सवाना के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती भारतीय दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। राष्ट्रपति ने बोत्सवाना सरकार के अनुरोध पर आवश्यक एआरवी दवाइयां उपलब्ध कराने के भारत के निर्णय के बारे में भी अवगत कराया।

दोनों राष्ट्रपतियों ने प्रेस के समक्ष वक्तव्य जारी किए।

सरदार पटेल राष्ट्र देवता...स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने की तगड़ी तारीफ, क्या बोले सीएम योगी?

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती के मौके पर गुजरात के केवडिया में चल रहे भारत पर्व में बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस आयोजन का हिस्सा बने।

अहमदाबादः (जीएनएस)। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बुधवार का दिन उत्तर प्रदेश के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम ने इसके बाद केवडिया में भारत पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज एकता नगर आने का सौभाग्य मिला है। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमें अपने भारत के अंदर 535 अलग देश के लिए वीजा बनवाकर जाना पड़ता। सरदार पटेल जी एक राष्ट्र के देवता के रूप में हैं मैं उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं और पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस वैसे एकता दिवस कार्यक्रम को 31 अक्टूबर के लिए शुरू किया है।

यूपी के डिप्टी सीएम आज भारत पर्व केवडिया गुजरात में सबसे बड़े पर्यटक स्थल पर आज हम सब एकत्र हुए हैं। भारत पर्व पर मैं पूरे प्रदेशवासियों और भारतवर्ष को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जिस ढंग से गुजरात का केवडिया धाम बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है।

और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार साहब की लगाई गई है। मैं ऐसे अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करता हूं और गुजरात सरकार का आभार प्रकट करता हूं और विशेष आभार और अभिनंदन पीएम मोदी को करता हूं कि उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृतियों संजोते हुए उन्होंने विरासत का एक बड़ा सम्मान करने का काम किया है।

क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

भारत पर्व के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात सदैव देश को एक राह दिखाने वाला राज्य रहा है...गुजरात भगवान सोमनाथ और भगवान नागेश्वर नाथ की पावन धरा है। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत की भूमि भी है। यह भारत के स्वाधीनता आंदोलन को स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली पावन धरा भी है।

पीएम मोदी ने संभव कर दिखाया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत', सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है, जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसकी कीमत चुकाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जो दूसरों के लिए असंभव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे संभव करके दिखाया। सीएम योगी ने कहा कि गुजरात भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन धरा है। योगी आदित्यनाथ के साथ इस दौरे में यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी मौजूद रहे।

15 नवंबर तक चलेगा भारत पर्व

केवडिया में भारत पर्व 15 नवंबर तक चलेगा। इसकी शुरूआत 1 नवंबर से हुई थी। इससे पहले 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। गुजरात के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर सीईओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमित अरोड़ा ने यूपी के सीएम और उप मुख्यमंत्रियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। सीएम योगी के दौरे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री जयवीर सिंह साथ में मौजूद रहे।

अल्पसंख्यक कार्य सचिव ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा की

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने छत्तीसगढ़ में

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान, सचिव ने राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति पंजीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, राज्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की पहलों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया, विस्फोट पीड़ितों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों को सजा दी जाएगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल जाकर हाल ही में लालकिले के पास हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना भी की।

विस्फोट घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जोर देकर कहा, "षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं, उन्हें सजा दी जाएगी।"

एक्स पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहाः

"एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिला। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

इस षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा!

नौसेना प्रमुख का संयुक्त राज्य अमेरिका दौरा

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 12 से 17 नवंबर, 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच मजबूत और स्थायी समुद्री साझेदारी को और मजबूत करना है, जो भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। नौसेना प्रमुख इस यात्रा के दौरान अमेरिकी युद्ध विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। वह अन्य वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद-प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापारो और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत बेड़े के कमांडर एडमिरल स्टीफन टी. कोहलर से भी मिलेंगे। यह बातचीत दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे समुद्री सहयोग की समीक्षा, स्तरीय-परिचालन संबंधों को बढ़ाने और सूचना साझा करने तथा समुद्री क्षेत्र जागरूकता के तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

इस यात्रा में अमेरिकी नौसेना के प्रमुख नौसैनिक संस्थानों और परिचालन कमांडों के साथ बैठकें भी होंगी।

वित्तीय सेवा सचिव ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

बैंकों ने स्थिर वृद्धि, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और मजबूत डिजिटल प्रदर्शन दर्ज किया

(जीएनएस)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में ₹93,675 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया; सकल एनपीए घटकर कई वर्षों के निचले स्तर 2.30% और शुद्ध एनपीए 0.45% पर आ गया, कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ रहा

कम लागत वाली जमाओं में वृद्धि को बनाए रखते हुए और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करते हुए एमएसएमई और कृषि को ऋण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और डेटा सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण विस्तार शामिल हैं

जनसमर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप ऋण मॉड्यूल लॉन्च किया गयाः विकसित भारत @2047 की दिशा में रोडमैप को दशार्ती सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मंथन 2025 पर रिपोर्ट जारी की गई

प्रविष्टि तिथिः 12 ठडश 2025 6:53ढट्ु८ ढक्ह ऊै

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव, श्री एम. नागराजू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन किया गया। बैठक में वित्तीय प्रदर्शन, परिसंपत्ति गुणवत्ता, वसूली और समाधान, डिजिटल परिवर्तन और सरकारी प्रमुख योजनाओं की प्रगति सहित प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की गई। यूआईडीएआई ने डिजिटल पहचान एकीकरण और डी-डुप्लीकेशन के लिए आधार के उपयोग पर एक प्रस्तुति दी। बैंकिंग में मानव एआई अभिसरण विषय पर भी चर्चा हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान ₹93,675 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल स्थिर वृद्धि को दशार्ता है। सितंबर 2025 तक कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ रहा, जिसमें अग्रिमों में 12.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और जमाओं में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर 2.30 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.45 प्रतिशत रह गया, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार को दशार्ता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नोटरी के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए, नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया

- गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विधि राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया सहभागी हुए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेलः-

- कानूनी प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी तथा ऑनेस्टी स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी की भूमिका महत्वपूर्ण है
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है
- सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य
- दस्तावेज अपलोड करने तथा आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन, समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी
- नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन होने से पर्यावरण की रक्षा होगी, पेपरलेस गवर्नेंस को वेग मिलेगा
- गुजरात के इतिहास में पहली बार 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी के रूप में नियुक्ति दी गई : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर, 12 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विधि विभाग तथा गुजरात बार काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नोटरी (लेख्य प्रमाणक) के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को बुधवार को गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्री पटेल ने राज्य में ई-नोटरी सिस्टम विकसित करने के लिए नोटरी पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साधारण व्यक्ति के हित को तथा उसकी सरलता को ईज ऑफ लिविंग के केन्द्र में रखा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया या याजोनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट का शासन मंत्र अपनाया है। यह कार्यक्रम गुजरात के विधि जगत में आज उसी मंत्र को साकार करने वाला अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विधि (कानून) का शासन महत्वपूर्ण नींव है। प्रधानमंत्री ने कानून के शासन के लिए समयानुरूप कानून प्रस्तुत करने का भगीरथ कार्य किया है। उन्होंने अंग्रेजों के समय के अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर कानूनी प्रक्रिया सरल बनाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सिंग शिक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श और अनुभव-साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया

नर्स और दाइयां भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का आधार और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव

भारत की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का श्रेय उसके नर्सिंग कार्यबल की शक्ति और प्रतिबद्धता को जाता है: वीके पॉल, सदस्य, नीति आयोग

भारत वैश्विक नर्सिंग कार्यबल में दुनिया के सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक के रूप में उभरा है: भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और जेएचपीईजीओ के सहयोग से भारत में नर्सिंग नीति प्राथमिकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श और अनुभव साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य नीतिगत संवाद को मजबूत करना और नर्सिंग तथा मिडवाइफरी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाना है।

कार्यशाला में देश भर के नीति निमार्ताओं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नियामकों, नर्सिंग शिक्षकों, पेशेवर संघों और विकास भागीदारों सहित प्रमुख हितधारकों को

एक मंच पर लाया गया। इस परामर्श का उद्देश्य वर्तमान में जारी पहलों की समीक्षा करना, उभरती चुनौतियों की पहचान करना और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप नर्सिंग प्रशासन, शिक्षा और कार्यबल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नवीन मॉडलों को साझा करना था।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि नर्सें और दाइयाँ भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का आधार और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आशा कार्यकताओं के साथ मिलकर, वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के हालिया सुधार, जिनमें राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) की स्थापना, योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम को अपनाना और नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने की पहल शामिल हैं, नर्सिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रमुख उपलब्धि हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के दौरान प्रत्येक राज्य से उभर कर आने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शक सुझावों के रूप में कार्य करना चाहिए तथा अन्य राज्यों को देश भर में नर्सिंग क्षेत्र में व्यापक अनुकरण और सुधार के लिए इन मॉडलों पर ध्यान देना चाहिए।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, प्रोफेसर वी. के. पॉल ने इस महत्वपूर्ण परामर्श के आयोजन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सराहना की। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिसका मुख्य कारण इसके नर्सिंग कार्यबल की क्षमता और समर्पण है। उन्होंने दोहराया कि नर्सिंग भारत की व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ है।

नर्सों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए, डॉ. पॉल ने कहा कि यह अभी भी ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। उन्होंने नर्सिंग शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और देखभाल एवं पेशेवर उत्कृष्टता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन पर अधिक जोर देने का आ'ान किया।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि डॉ. पेडेन ने नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्र में देश की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक नर्सिंग कार्यबल में दुनिया के सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक के रूप में उभरा है।

फियो ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत किया: यह भारत के निर्यात इकोसिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है

नई दिल्ली, 12 नवंबर, 2025: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करता है। यह केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टरों के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला यह मिशन, कई निर्यात संवर्धन योजनाओं को एक व्यापक, परिणाम-आधारित और डिजिटल रूप से संचालित ढाँचे में समेकित करके एक बड़े संरचनात्मक सुधार का प्रतीक है।

इस घटनाक्रम पर बोलते हुए फियो के अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने कहा, "निर्यात संवर्धन मिशन भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्तीय और गैर-वित्तीय युक्तियों को एक एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत लाकर, यह मिशन वैश्विक व्यापार गतिशीलता के लिए आवश्यक निरंतरता, लचीलापन और जवाबदेही प्रदान करता है। यह विशेष रूप से एमएसएमई को सशक्त बनाएगा, जिन्हें अक्सर किफायती वित्त और अनुपालन सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।"

मिशन की समावेशिता पर प्रकाश डालते हुए, श्री रल्हन ने कहा, "ईपीएम उन संरचनात्मक चुनौतियों - वित्त तक सीमित पहुँच और उच्च अनुपालन लागत से लेकर कमजोर ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स बाधाओं तक- का समयोचित समाधान है, जिन्होंने लंबे समय से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कुंद किया है। इन मुद्दों से सीधे निपटकर, यह पहल निर्यात की गति को बनाए रखने, रोजगार की रक्षा करने और भारत के निर्यात आधार को नए भौगोलिक क्षेत्रों और उभरते सेक्टरों में विविधता प्रदान करने में मदद करेगी।"

ईपीएम के तहत, कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों जैसे हालिया वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे निरंतर निर्यात ऑर्डर और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो पारदर्शिता, गति और सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं का डिजिटल प्रबंधन करेगा।

श्री रल्हन ने कहा, "मौजूदा व्यापार प्रणालियों के साथ मिशन का डिजिटल एकीकरण निर्यातकों के अनुभव को बदल देगा - कागजी कार्रवाई को कम करेगा, समन्वय में सुधार करेगा और समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा। यह विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक स्मार्ट, तकनीक-सक्षम निर्यात इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

फियो अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि निर्यात संवर्धन मिशन न केवल निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देगा, बल्कि विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में रोजगार सृजन को भी उत्प्रेरित करेगा, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना न केवल को-लैटेरल ऋण प्रदान करेगी, बल्कि अतिरिक्त वित्तीय तरलता भी प्रदान करेगी, जो समय की मांग है।

श्री रल्हन ने कहा 'फियो मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी इकोसिस्टम और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। यह भारतीय निर्यात के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है और हमें इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ ग्रहण करना चाहिए।'

कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 12 नवंबर, 2025 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी ने की। बैठक में माननीय सांसदगण, अन्य सदस्यगण, सचिव (कोयला) तथा कोयला मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय एकता और जन-मन को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी भाषा की सरलता और सहजता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। आज हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि माननीय सदस्यों से जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, कोयला मंत्रालय द्वारा उन पर अमल किया जाएगा।

उक्त बैठक में पीपीटी के माध्यम से कोयला मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। इसके अलावा, राजभाषा के प्रति 'निष्ठा की प्रतिष्ठा' हेतु माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी द्वारा कंपनी प्रमुखों एवं राजभाषा अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस बैठक में माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी द्वारा राजभाषा विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर को समर्पित, कोयला मंत्रालय की प्रथम पत्रिका 'अभिव्यक्ति', का भी विमोचन किया गया। मंत्रालय समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने का पूर्ण प्रयास करेगा।

डीडीडब्ल्यूएस ने जल जीवन मिशन के तहत 'जनभागीदारी के लिए संचार और पीआरए टूल्स ' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कार्यशाला को संबोधित किया और कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिरता के लिए सहभागी टूल्स के सह-निर्माण में आरडब्ल्यूपीएफ साझीदारों और राज्यों की सक्रिय भागीदारी

(जीएनएस)।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने 12 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में 'सामुदायिक सहभागिता (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए संचार और पीआरए टूल्स' पर ग्रामीण वाश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल, डीडीडब्ल्यूएस के सचिव श्री अशोक के.के. मीणा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन, एनजेजेएम की संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति मीणा नाइक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक श्रीमती ऐश्वर्या सिंह, डीडीडब्ल्यूएस, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(एमओएएफडब्ल्यू), जल संसाधन विभाग, राष्ट्रीय जल मिशन, पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीडब्ल्यूजीबी), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी), भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, आरडब्ल्यूपीएफ के सदस्य और विकास साझीदार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यशाला की शुरूआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रमुख पहलों के अनावरण के साथ हुई। इनमें शामिल हैं:

स्रोत स्थिरता के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस)

जेजेएम पंचायत डैशबोर्ड

सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की पहली कड़ी - "स्वच्छ सुजल गांव की कहानीः रेडियो की जुबानी"

ग्रामीण भारत में समुदाय-प्रबंधित पाइप जल प्रणालियों पर लघु पुस्तिका - "जन भागीदारी से हर घर जल"

केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री के इस विजन के जीवंत प्रतीक हैं कि "जन भागीदारी से ही जन कल्याण संभव है।" उन्होंने रेखांकित किया कि 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को पानी लाने के झंझट से मुक्ति मिल गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण भारत प्रतिदिन 5.5 करोड़ व्यक्ति-घंटे बचा सकता है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई "जल संचय जन भागीदारी" पहल दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और बोरवेल कायाकल्प पर केंद्रित है। श्री पाटिल ने डिजिटल नवाचार और पारदर्शिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और उन्हें जल संसाधनों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने के चल रहे प्रयासों को रेखांकित किया।

अपने उद्घाटन भाषण में, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक के.के. मीणा ने इस बात पर बल दिया कि जनभागीदारी ही इस मिशन का मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को सामुदायिक स्वामित्व, स्थानीय निर्णय प्रक्रिया और स्थिरता पर आधारित सर्वाधिक बुनियादी स्तर के कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा, "लोग लाभार्थी नहीं हैं; वे अपनी जल प्रणालियों के संरक्षक हैं।"

सचिव ने संचार और व्यवहार परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे टूल्स तैयार करना है जो भागीदारी को ठोस कार्रवाई में बदल सकें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगति के दो प्रमुख स्तंभ बन गए हैं।

क्यूसीआई और बीएचईएल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त रूप से अंतर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन का आयोजन गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए किया

(जीएनएस)।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के सहयोग से नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अंतर पीएसयू गुणवता मंथन का आयोजन किया।

कार्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं में संरचित ढाँचों और उत्कृष्टता मॉडलों के माध्यम से राष्ट्रीय गुणवत्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्यूसीआई की भूमिका पर जोर दिया गया। भाग लेने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने सिक्स सिग्मा, लीन, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस (टीपीएम), डिजिटल ऑटोमेशन और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव और पहलों को साझा किया। इस संवादात्मक सत्र ने प्रथाओं के मानकीकरण और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद की।

इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सहयोग और पारस्परिक ज्ञान को मजबूत करना है, जो कि क्यूसीआई के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और गुणवत्ता-संचालित संस्थानों के विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों में योगदान देगा।

बीएचईएल के कॉर्पोरेट गुणवत्ता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता प्रमुख डॉ. दुर्गेश सी. गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय प्रमाणन

निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) - क्यूसीआई के सहयोग से, बीईएल, बीपीसीएल, ईआईएल, गेल, आईओसीएल, पीजीसीआईएल और टीएचडीसी सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एक मंच पर आए। इस मंच ने गुणवत्ता प्रबंधन, व्यावसायिक उत्कृष्टता, परिचालन दक्षता, आपूर्ति श्रृंखला गुणवत्ता, डिजिटल परिवर्तन और स्थिरता-उन्मुख प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाया।

क्यूसीआई के अध्यक्ष, श्री जैक्सय शाह ने कहा कि क्यूसीआई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र सहित भारतीय उद्योग जगत में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन औद्योगिक परिचालनों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक कदम है।

बीएचईएल के निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), श्री एस.एम. रामनाथन ने अपने मुख्य भाषण में भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजाइन से लेकर वितरण तक सरलता और प्रभावशीलता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि गुणवत्तापूर्ण परिणाम, बेहतर ग्राहक संतुष्टि और परिचालन दक्षता में बदल सकें।

एनएबीसीबी के अध्यक्ष डॉ. रवि पी. सिंह ने सभी उद्यमों में एक विश्वसनीय और सक्षम गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय गुणवत्ता प्रणालियों की विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम का समापन क्यूसीआई और बीएचईएल के संयुक्त सत्र के साथ हुआ, जिसमें संस्थागत सहयोग के संभावित मॉडलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुकूलित गुणवत्ता साझेदारी और परिपक्वता संवर्धन कार्यक्रम शामिल थे। अंतर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में गुणवत्ता-उन्मुख शासन और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए क्यूसीआई और बीएचईएल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने 'ऑपरेशन बुलियन ब्लेज' के तहत मुंबई में सोने की तस्करी करके उसे पिघलाने वाले एक बड़े गिरोह का पदार्फाश किया; 11.88 किलोग्राम सोना जब्त किया गया और 11 लोग गिरफ्तार किए गए

(जीएनएस)।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने "ऑपरेशन बुलियन ब्लेज" के तहत मुंबई में सोने की तस्करी, उसे गुप्त भट्टियों में पिघलाने और परिष्कृत सोने को अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेचने में शामिल एक संगठित गिरोह का पदार्फाश किया है।

डीआरआई अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, 10.11.2025 को मुंबई में चार गुप्त स्थानों पर सोने को पिघलाने वाली दो अवैध इकाइयों और सोने को अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेचने दो अपंजीकृत दुकानों की तलाशी ली।

दोनों अवैध भट्टियों में तस्करी किए गए सोने को मोम और अन्य रूपों में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था थीं। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध भट्टियां चलाने वालों को हिरासत में ले लिया और मौके पर ही 6.35 किलोग्राम सोना बरामद किया। इसके बाद, तस्करी का सोना और पिघली हुई छड़ें स्थानीय खरीदारों को बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दुकानों की भी तलाशी ली गई, जिसमें से एक दुकान

से 5.53 किलोग्राम अतिरिक्त सोने की छड़ें बरामद हुईं।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने 15.05 करोड़ रुपये मूल्य का 11.88 किलोग्राम 24 कैरेट सोना और 13.17 लाख रुपये मूल्य की 8.72 किलोग्राम चांदी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त की।

सोने की तस्करी, गलाने और अवैध बिक्री में शामिल मास्टरमाइंड सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह मास्टरमाइंड द्वारा अपने पिता, एक प्रबंधक, सोना पिघलाने वाले चार व्यक्तियों, तस्करी किए गए सोने का रिकॉर्ड रखने वाले एक एकाउंटेंट और सोने के वितरण का काम संभालने वाले तीन डिलीवरी कर्मियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। सभी आरोपियों को मुंबई के संयुक्त वित्तीय आयुक्त (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सोने की तस्करी और अवैध बिक्री के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी, जो देश की स्वर्ण आयात नीति का घोर उल्लंघन है और इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाना था। डीआरआई राजस्व और बाजारों को नुकसान पहुंचाने वाले और राजकोषीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले उन सभी संगठित तस्करी नेटवर्कों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीआरआई देश की आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा करके निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित करता है।

मामले की आगे की जांच जारी है।

रक्षा उत्पादन सचिव ने कहा - विघटनकारी तकनीकों से प्रेरित आधुनिक क्षमताओं और स्टार्ट-अप्स तथा नवप्रवर्तकों के साथ गहन सहयोग की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका

(जीएनएस)।

सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार ने देश की तकनीकी क्षमता को सशक्त बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टार्ट-अप्स तथा नवप्रवर्तकों के साथ व्यापक सहयोग का आ'ान किया है। वे 12 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नए तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति को गति देने और रक्षा प्रणालियों के तकनीकी आधार को सुदृढ़ करने के लिए युवा उद्यमियों तथा नवप्रवर्तकों के साथ साझेदारी के महत्व पर बल दिया।

सचिव (रक्षा उत्पादन) ने कहा कि आज की अत्याधुनिक क्षमताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नवाचार की गति तेज करने और व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच विचारों एवं सूचनाओं का निर्बाध तथा प्रभावी आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है।

संजीव कुमार ने आधुनिक युद्ध की तैयारियों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) और प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) जैसी गतिविधियां नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्टार्ट-अप्स तथा एमएसएमई को सशक्त बनाया जा रहा है। इन सभी के माध्यम से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने मार्ग को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है।

'रक्षा क्षमता विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग' विषय पर आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सशस्त्र बलों के नेतृत्व, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

संवैधानिक रूप से पाकिस्तान बढ़ा रहा सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर की ताकत

पाकिस्तान का इतिहास सैन्य शासन से भरा हुआ है। यहां चुनी हुई सिविलियन सरकार थोड़ा समय चलती है फिर कोई न कोई जनरल शासन का तख्ता पलट देता है। ताजा उदाहरण पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही ले लीजिए। पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की सरकार भारत के ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए संवैधानिक बदलाव की तैयारी में है। जिसमें सेना प्रामुख आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) बनाने की योजना है, इससे उनकी शक्तियां संवैधानिक रूप से बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ से लगता है कि एक बार फिर अपने सेना प्रामुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का पैसला किया है। 8 नवम्बर को संसद में पेश 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के जरिए रक्षा बलों के प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस) सीडीएफ नामक एक नया अत्यंत शक्तिशाली पद सृजित कर दिया गया, जो सीधे मुनीर के लिए ही रचा गया प्रातीत होता है। यह पदोन्नति मई 2025 में भारत के साथ हुए चार दिवसीय संघर्ष के बाद मिले फील्ड मार्शल के सम्मान के ठीक छह महीने बाद हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आतंकवाद के कथित संरक्षक मुनीर को यह दोहरी मेहरबानी आखिर क्यों? क्या मई का संघर्ष ही वह कारनामा है या फिर पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और सैन्य तानाशाही को मजबूत करने की साजिश? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनीर को ओसामा बिन लादेन इन सूट कहा जाता है और अब यह प्रामोशन उसके दोहरे चेहरे-एक तरफ आतंक के प्रायोजक, दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता के हामी-की ओर उजागर कर रहा है। संवैधानिक संशोधन : मुनीर की कमान को संवैधानिक छतरी लेकिन लोकतंत्र पर सहमे कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद सीनेट में पेश किए गए इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 243 में व्यापक बदलाव प्रास्तावित है, जो सशस्त्र बलों की कमान संरचना को पूरी तरह पुनर्गठित कर देते हैं। यह 27वां संविधान विधेयक पाकिस्तान के संविधान में एक बड़ा बदलाव लाने वाला प्रास्तावित कानून है। इस संशोधन में अनुच्छेद 243 संशोधन भी शामिल है, जिसके तहत रक्षा बलों के प्रमुख का पद औपचारिक रूप से सेना प्रमुख को सौंप दिया जाएगा और उन्हें आजीवन फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया गया है। अगर यह बिल पास हुआ तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर आजीवन फील्ड मार्शल के पद पर रहेंगे। हालांकि इसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि यह बदलाव देश की रक्षा आवश्यकताओं और सैन्य कमानसंर चना को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सीडीएफ का जो मसौदा पेश किया है, वह भारत के चीफ डिपेंस ऑफ आमा स्टॉफ (सीडीएस) के प्रारूप की चोरी की है। मजलिस-ए-वहदत-एमुस्लेमीन पार्टा प्रामुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं पंगू हो चुकी हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में किसान भाई-बहनों को 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार' प्रदान किए

पीपीवीएफआरए अधिनियम की रजत जयंती और प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस पर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ

विलुप्त हो रहे बीजों के संरक्षण की दिशा में पीपीवीएफआरए अधिनियम की भूमिका महत्वपूर्ण- श्री चौहान

किसानों को पीपीवीएफआरए अधिनियम के बारे में और अधिक जागरुक किया जाना चाहिए- श्री शिवराज सिंह

बीजों की नई किस्म जरूरी लेकिन पुराने बीजों की किस्मों को भी बचाना होगा; केंद्रीय कृषि मंत्री

पीपीवीएफआरए अधिनियम में सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन भी किया जाएगा- श्री चौहान

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित सी. सुब्रमण्यम सभागार में 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह और पीपीवीएफआरए अधिनियम, 2001 के रजत जयंती व पीपीवीएफआरए (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण) के 21वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भागीदारी की और चयनित किसान भाई-बहनों को पुरस्कृत किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना के कम्यूनिटि सीड बैंक, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल के शिक्षा निकेतन, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, असम के सीआरएस-एनए दिहिंग तेंगा उन्नयन समिति, उत्तराखंड के श्री भूपेंद्र जोशी, केरल के श्री टी. जोसेफ, श्री लक्षण प्रमाणिक, श्री अनंतमूर्ति जे, बिहार के श्री नकुल सिंह, उत्तराखंड के श्री नरेंद्र सिंह सहित विभिन्न अनेक श्रेणियों में किसान भाई-बहनों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि पीपीवीएफआरए प्राधिकरण ने पिछले 20 वर्षों में अद्भुत काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि पद्धति अत्यंत प्राचीन है। कृषि हमारे देश का मूल रहा है। अनेक बीजों की किस्में पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बीते वर्षों में कुछ किस्में विलुप्त होने की कगार पर आ गई थीं, जिन्हें सहेजने में किसान भाई-बहनों ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के माध्यम से बीज संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 15 लाख रुपये तक की धनराशि देने का प्रावधान किया है। श्री चौहान ने कहा कि बीज सबसे बड़ी पूंजी है। बीज हमारा मौलिक अधिकार है। नई किस्मों को बढ़ावा देना जरूरी लेकिन पुरानी किस्मों को भी बचाना है, दोनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री ने पीपीवीएफआरए अधिनियम में नए सुझावों को शामिल करने के प्रस्ताव की भी चर्चा की और कहा कि जहां आवश्यक होगा वहां अधिनियम में नए सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन किया जाएगा।

आगे, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम के बारे में अभी भी किसानों को कम जानकारी है पंजीकरण को लेकर भी कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। पारदर्शिता के स्तर पर भी कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों तक अधिनियम का वास्तविक लाभ का हिस्सा भी सीमित रूप से ही पहुंच पाता है जिस दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसी संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए पीपीवीएफआरए के माध्यम से कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सशक्त प्रणाली पौधों और बीजों के संरक्षण में और अधिक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए किसान कल्याण में नए अध्याय जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने पीपीवीएफआरए अधिनियम का अन्य कानूनों के साथ समन्वय और वैज्ञानिक डेटाबेस को मजबूत करने की भी बात कही।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक दृष्टि से किसानों के द्वारा पौधों और बीजों की किस्मों को संरक्षित करने के उपायों की चर्चा की और भी रेखांकित किया।

कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने मडुआ जैसी विभिन्न प्रजातियों के बीजों के संरक्षण पर बल देते हुए संगठन से इस दिशा में और सक्रिय प्रयास करने का आ'ान किया। उन्होंने मडुआ के समान अन्य पौधों की प्रजातियों के औषधीय महत्व को भी रेखांकित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू, पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, पीपीवीएफआरए के रजिस्ट्रार-जनरल डॉ. डी. के. अग्रवाल उपस्थित रहे।

पृष्ठभूमिः

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य नई पौध किस्मों के प्रजनकों को उनके नवाचार के लिए अधिकार प्रदान करना तथा किसानों के पारंपरिक ज्ञान और योगदान की रक्षा करना है। यह प्राधिकरण नई पौध किस्मों का पंजीकरण करता है, किसानों और समुदायों को उनके संरक्षण कार्य हेतु पुरस्कृत करता है तथा राष्ट्रीय पौध किस्म अभिलेख (ठं३ङ्गल्लं' फ्ीर२३ी१ ङ्ग ढ'ल्ल३ ४ं१्री३ी२) का संधारण करता है। साथ ही यह किसानों को बीज बचाने, बोने और पुनः उपयोग करने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है, जिससे अनुसंधान, नवाचार और कृषि जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।

कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दी

20, 20,000 करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना

एनसीजीटीसी के माध्यम से 100 प्रतिशत ऋण गारंटी

एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों निर्यातकों को लाभ

सीजीएसई से तरलता, बाजार विविधीकरण, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने को मंजूरी दे दी। इससे राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा ताकि पात्र निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सके।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः

इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से करेगा ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को एमएलआई अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान कर सके। डीएफएस सचिव की अध्यक्षता में गठित एक प्रबंधन समिति इस योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

प्रमुख प्रभावः

इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के बढ़ने और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण को मदद मिलने की उम्मीद है। सीजीएसई के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण को सुलभ करके, यह योजना तरलता को मजबूत करेगी, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करेगी और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को सुदृढ़ करेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की यात्रा को और मजबूती मिलेगी।

पृष्ठभूमिः निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 21 प्रतिशत रहा। विदेशी मुद्रा भंडार में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नियातीन्मुखी उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और एमएसएमई कुल निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान करते हैं। निरंतर निर्यात वृद्धि भारत के चालू खाता संतुलन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक रही है।

निर्यातकों को अपने बाजारों में विविधता लाने और भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर वित्तीय सहायता और पर्याप्त समय प्रदान करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, अतिरिक्त तरलता सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय सरकारी योजना से व्यावसायिक वृद्धि सुनिश्चित होगी और बाजारों का विस्तार भी संभव होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

(जीएनएस)।

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11-12 नवंबर 2025 तक भूटान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा की।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर 2025 को चांगलिमथांग में महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो की 70वीं जयंती के अवसर पर भूटान के लोगों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में जारी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लिया। भूटान नरेश ने महोत्सव के दौरान सार्वजनिक पूजा-अर्चना के लिए थिम्पू में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की उपस्थिति की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम नरेश और महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो के साथ उपस्थित जनसमूह से भेंट करते हुए और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोबगे के साथ वातार्लाप किया।

महामहिम नरेश ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट में हुई अनमोल जान-माल की दुखद क्षति पर भूटान की शाही सरकार और जनता की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने भूटान के समर्थन और एकजुटता के संदेश के प्रति आभार जताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सहित भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति भारत के निरन् तर समर्थन की पुष्टि की और भूटान को उसकी प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को हासिल करने और सभी क्षेत्रों में सतत विकास को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भूटान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और देश के विकास में उनके योगदान के लिए भारत की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए महामहिम के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त

किया। उन्होंने गेलेफू में निवेशकों और आगंतुकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हतिसार में एक आव्रजन जांच चौकी स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। महामहिम ने ग्यालसुंग अकादमियों के निर्माण के लिए भारत सरकार के सहयोग की सराहना की।

महामहिम नरेश और प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर 2025 को भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की गरिमामय उपस्थिति में, 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-क्क जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह परियोजना जलविद्युत के क्षेत्र में भूटान और भारत के बीच मैत्री और अनुकरणीय सहयोग का प्रमाण है। उन्होंने पुनात्सांगछू-क्क से भारत को बिजली के निर्यात की शुरूआत का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने मार्च 2024 की ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर भी संतोष व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-क जलविद्युत परियोजना के मुख्य बांध ढांचे पर कार्य फिर से शुरू करने के संबंध में बनी सहमति का स्वागत किया और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। पुनात्सांगछू-क जलविद्युत परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर यह दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी।

उन्होंने भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया। भूटानी पक्ष ने भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा 40 अरब रुपये के रियायती ऋण सहायता की घोषणा की सराहना की।

दोनों पक्षों ने एकीकृत चेक पोस्टों की स्थापना सहित सीमा पार संपर्क में सुधार और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विस्तार के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने नवंबर 2024 में दर्रांगा में आव्रजन जांच चौकी और मार्च 2025 में जोगीगोफा में अंतदेर्शीय जलमार्ग टर्मिनल और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के संचालन का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने सितंबर 2025 में सीमा पार रेल संपर्क (गेलेफू-कोकराझार और समत्से-बानरहाट) की स्थापना पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना संचालन समिति की स्थापना का भी स्वागत किया।

भूटानी पक्ष ने भूटान को आवश्यक वस्तुओं और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। दोनों पक्षों ने नई व्यवस्था के अंतर्गत भारत से उर्वरकों की पहली खेप के आगमन का स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने एसटीईएम, फिनटेक और अंतरिक्ष के नए क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यूपीआई के दूसरे चरण पर जारी कार्य का स्वागत किया, जो भारत आने वाले भूटानी आगंतुकों को क्यूआर कोड स्कैन करके स्थानीय मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने भूटान में एसटीईएम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में भारतीय शिक्षकों और नर्सों के अमूल्य योगदान को भी स्वीकार किया।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को है ये गंभीर बीमारी, कैसे आईसीयू तक पहुंचे एक्टर? जानें 'ही-मैन' की तबीयत बिगड़ने का पूरा सच

(जीएनएस)।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 89 वर्षीय अभिनेता को कुछ दिनों पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह डॉक्टरों की निगरानी में थे।

धर्मेंद्र की तबीयत में हुआ सुधार

अब डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार हुआ है और उन्हें गत 12 नवंबर2025 (बुधवार) सुबह करीब साढ़े सात बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि अब उनके पिता का इलाज और रिकवरी घर पर ही जारी रहेगी।

कैसे बिगड़ गई थी धर्मेंद्र की हालत?

-मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि एक्टर धर्मेंद्र की हालत पिछले कुछ दिनों से काफी नाजुक बनी हुई थी। उन्हें सांस फूलने की शिकायत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं गत 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) को एक्टर के अस्पताल में ही निधन की बात सामने आने लगी थी।

-वहीं एक्टर के निधन की बात सामने आते ही बेटी ईशा देओल ने साफतौर पर इस बात का खंडन किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि उनके पिता धर्मेंद्र की मौत नहीं हुई है। वह अस्पताल में हैं और उनकी हालत स्थिर है। वहीं एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी ने भी मौत की बात को झूठा बताया था।

हेमा मालिनी तो इस तरह की फर्जी खबर फैलाने वालों को सरेआम लताड़ने भी लगी थीं। जानकारी के अनुसार गत 10 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई थी। उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा धर्मेंद्र के परिवार वालों के अलावा कई बड़े सेलेब्स जैसे शाहरुख खान सलमान खान, लिजेंड्री एक्टर से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे।

-आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि 89 साल के धर्मेंद्र को सांस फूलने की शिकायत के चलते एडमिट कराया गया था। पहले उन्हें आईसीयू में रखा गया था लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था।

-अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। हालांकि उम्र अधिक होने पर ऐसा होना सामान्य है। डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है कि धर्मेंद्र को फेफड़ों में परेशानी हो रही थी। ऐसे में उन्हें पिछले कुछ समय से सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी।

क्या होता है डिस्पनिया

-आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ती रहती हैं। सांस लेने में तकलीफ होने वाली बीमारी को डिस्पनिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ये एक लक्षण है जिसका मतलब है सांस लेने में असुविधा या सांस न ले पाना और ये कई अलग-अलग बीमारियों का संकेत हो सकता है।

-दिल और फेफड़ों की बीमारियां डिस्पेनिया के सामान्य कारण हैं। डिस्पनिया, जिसे आम भाषा में सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ कहते हैं, सांस लेने में असहजता या कठिनाई की व्यक्तिपरक अनुभूति है। यह अक्सर हृदय या फेफड़ों की समस्याओं का लक्षण होता है, लेकिन यह अस्थमा, निमोनिया, एनीमिया, चिंता या शारीरिक परिश्रम के कारण भी हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश से भेंट की और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से भेंट की।

प्रधानमंत्री ने चौथे नरेश की 70वीं जयंती के अवसर पर बधाई दी और भारत सरकार एवं देश के नागरिकों की ओर से महामहिम नरेश के उत्तम स्वास्थ्य एवं कुशलता के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने भारत-भूटान मैत्री को और सुदृढ़ बनाने में उनके नेतृत्व, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए चौथे नरेश का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने

द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधनों को रेखांकित किया जो दोनों देशों के लोगों को करीब लाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी थिम्पू में जारी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के एक भाग के रूप में चांगलिमथांग स्टेडियम में कालचक्र दीक्षा समारोह में भूटान नरेश, भूटान के चौथे नरेश और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। इस प्रार्थना की अध्यक्षता भूटान के मुख्य मठाधीश परम पावन जे खेंपो ने की।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा - विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टरों को - सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है।

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित संरचना प्रदान करेगा। ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती आवश्यकताओं का त्वरित प्रत्युत्तर हो सकता है।

ईपीएम एक सहयोगात्मक ढांचे पर आधारित है जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से प्रचालित होगाः

निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात लेनदारी लेखा क्रय (फैक्टरिंग), संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहायता जैसे कई साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है।

निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं। इसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतदेर्शीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार खुफिया और क्षमता निर्माण पहलें शामिल हैं।

ईपीएम प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं जैसे कि ब्याज समकरण योजना (आईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) को समेकित करता है और उन्हें समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के साथ संयोजित करता है।

यह मिशन उन संरचनात्मक चुनौतियों का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो भारतीय निर्यात को बाधित करती हैं। इनमें शामिल हैंः

सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,

अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के साथ अनुपालन की उच्च लागत,

अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच और

आंतरिक और कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी हानि।

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित सेक्टरों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। ये युक्तियां निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, रोजगारों की रक्षा करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें आवेदन से लेकर वितरण तक सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन विद्यमान व्यापार प्रणालियों के साथ एकीकृत एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।

प्रसिद्ध शायर , पत्रकार और अदीब डॉक्टर तारिक कमर पर पीएच.डी. कस्बा सिरसी के काशिफ रजा को मिली डॉक्टरेट की डिग्री

संभल, (जीएनएस)। कस्बा सिरसी का शुमार उन इल्मी और अदबी बस्तियों में किया जाता है जिन्होंने अतीत से लेकर आज तक हर दौर में इल्म और अदब की परवरिश में अहम किरदार अदा किया है और जहाँ के कलमकारों ने पूरी दुनिया में अपनी बरतरी को तस्लीम करवाया है। इसी सिलसिले की एक और अहम कड़ी की शक्ल में जनाब काशिफ रजा का नाम भी जुड़ गया है।

काशिफ रजा ने उर्दू में पीएच.डी. पूरी करके अपना नाम भी सिरसी , संभल और करीबी हलकों के डॉक्टरों की फेहरिस्त में दर्ज करा लिया है। उन्होंने अपना शोधकार्य तहकीकी मकाला संभल के मशहूर व मारूफ शायर, सहाफी और नस्र निगार जनाब डॉक्टर तारिक कमर के इल्मी, अदबी और फनी जहात पर राजस्थान के अलवर स्थित यूनिवर्सिटी के शौबा-ए-उर्दू के सरबराह प्रोफेसर सैयद आसिफ जकरिया की निगरानी व सरपरस्ती में मुकम्मल किया। डॉक्टर काशिफ रजा की तहकीक का मौजू 'जदीद गजल ओ नज्म की सम्त ओ रफ़्तार और तारिक कमर' था।

वाजेह रहे कि डॉक्टर तारिक कमर की शख्सियत एक बेहतरीन शायर व अदीब की हैसियत से आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद व मुमताज पहचान रखती है। चार शेरी मजमूओं समेत मुख़्तलिफ मौजूआत पर डॉक्टर तारिक कमर की अब तक दस किताबें शाया हो चुकी हैं। वे संभल के एक निहायत मुफ़्तखर, मुहज्जब और इल्मी खानवादा-ए-सादात से ताल्लुक रखते हैं।

और संभल के डॉ नसीम साहब को अपना गुरू मानते हैं । इससे कब्ल भी डॉक्टर तारिक कमर की शख्सियत और उनके फनी जहात पर मअरूफ अदीबा व जाकिरा मुहतर्मा डॉक्टर किश्वर जहाँ जैदी ने एक जखीम किताब ब -उनवान 'गंगा-जमुना के साहिलों पर डॉक्टर तारिक कमर' तसनीफ की थी। इल्मी व अदबी दुनिया में इस किताब को बहुत पसंद किया गया था

डी.लिट. और पीएच.डी. की अहम डिग्रियाँ हासिल करने वाले डॉक्टर तारिक कमर तीन विषयों — उर्दू, अंग्रेजी और जर्नलिज्म में भी मास्टर्स डिग्रियाँ हासिल कर चुके हैं। सिर्फ. इतना ही नहीं, उन्होंने एक बेहतरीन उर्दू सफीर, शायर व अदीब की हैसियत से बीस से ज्यादा मुल्कों में हिंदुस्तान की मौतबर नुमाइंदगी की है। वे इस समय एम.एन.सी. मीडिया कम्युनिकेशन के अंग्रेजी शोबे में अहम सहाफती ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रहे हैं और इल्मी व अदबी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं।

काशिफ रजा की पीएच.डी. मुकम्मल होने पर सिरसी और आस पास के इल्मी व अदबी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोग उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम भी इदारे की जानिब से जनाब डॉक्टर काशिफ रजा को इस बेहतरीन तहकीकी मकाले के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं।

एनएसडीएल ने विदेशी निवेशकों के लिए बाजार में प्रवेश को आसान बनाने के लिए नया एफ पी आई - एफ वी सी आई पोर्टल लॉन्च किया

मुंबई, (जीएनएस)। 12नवंबर, 2025: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने आज अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पोर्टल को सफलतापूर्वक नया रूप देने और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की है। यह सभी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे विदेशी निवेशकों के लिए भारत के सिक्योरिटी बाजारों में रजिस्ट्रेशन और नियमों के पालन को आसान, तेज और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

मुंबई में आयोजित एनएसडीएल के 9वें नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागी सम्मेलन के दौरान, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की कार्यकारी निदेशक, डॉ. रुचि चोजेर ने 7 नवंबर, 2025 को अपग्रेड किए गए पोर्टल को लॉन्च किया। इस अवसर पर सेबी एनएसडीएल के एमडी एवं सीईओ, श्री विजय चंडोक; एनएसडीएल के के गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।

विदेशी निवेशकों के लिए सभी सुविधाएँ एक ही जगह उपलब्ध होंगीः बिल्कुल नए स्वरूप में पेश किया गया यह प्लेटफॉर्म एफ पी आई और एफ वी सी आई के रजिस्ट्रेशन और कामकाज को एक ही इंटरफेस पर लाता है, जिससे बार-बार लॉगिन करने और मैन्युअल प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं रहती है।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसी विदेशी कंपनियाँ हैं, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं और भारत की इक्विटी, बॉन्ड्स तथा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाती हैं, जिससे पूंजी बनाने और बाजार में पैसे का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है।

ड्ड विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफ वी सी आई) ऐसी विदेशी कंपनियाँ हैं, जो वेंचर कैपिटल फंड्स या गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में पैसा लगाती हैं, जिससे इनोवेशन के साथ-साथ नए उद्यम शुरू करने के जज्बे को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य विशेषताएँ और सुधार

- रजिस्ट्रेशन में आसानीः हर कदम पर स्पष्ट निर्देश, वेरीफिकेशन और मददगार सुझाव इस पूरी प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाते हैं।
- पता लगाने की सुविधाः आवेदन पर नजर रखने और ऑडिट ट्रेल्स से पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।
- सभी सुविधाएँ एक जगह उपलब्ध कराने वाला प्लेटफॉर्मः एफ पी आई और एफ वी सी आई रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही इंटरफेस होने से दोहराव कम होता है और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया तेज होती है।
- पी ए एन अनुरोध प्रक्रिया का स्वचालनः ए पी आई को प्रोटीन और एपीआई सेतु के साथ जोड़ने से काम पूरा होने का समय घटकर 1 से 2 दिन रह जाता है।
- टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजाइनः इसे एंगुलर, डॉटनेट कोर और एस क्यूं एल सर्वर पर बनाया गया है, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और यह 3 से 5 सेकंड में लोड हो जाए।

इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए, सेबी की कार्यकारी निदेशक, डॉ. रुचि चोजेर ने कहा, "ये नया प्लेटफॉर्म इस बात को दर्शाता है कि भारतीय बाजार के लिए सेबी का विजन बेहद सरल एवं निवेशकों के लिए अनुकूल है — एक ऐसा सिस्टम जो कारगर, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो।"

एन एस डी एल के एमडी एवं सीईओ, श्री विजय चंडोक ने कहा, "नए सिरे से तैयार किए गए एफ पी आई और एफ वी सी आई पोर्टलों के लॉन्च में हमारी प्रगति की झलक दिखाई देती है — बात सिर्फ. पोर्टल को अपग्रेड करने की नहीं है; बल्कि यह दर्शाता है कि एन एस डी एल अपने सभी भागीदारों को विश्व-स्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये सक्षम बनाने के संकल्प पर कायम है।"

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, एन एस डी एल के मुख्य व्यवसाय अधिकारी, श्री समीर पाटिल ने कहा, "असली प्रगति तो प्रक्रिया को सरल बनाने में छिपी होती है।

यह प्लेटफॉर्म उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मायबिज बाय मेकमायट्रिप और स्विगी के बीच गठबंधन

लखनऊ। मेकमायट्रिप के एसएएएस-आधारित कॉरपोरेट बुकिंग प्लेटफॉर्म मायबिज और भारत के अग्रणी ऑन-डिमांड सुविधा प्लेटफॉर्म स्विगी ने आज एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य देश भर में लाखों कॉरपोरेट यात्रियों के लिए भोजन से जुड़े व्यय प्रबंधन को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। टेक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ मायबिज भारत में कॉरपोरेट यात्रा के प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित है और 75,000$ कॉरपोरेट्स और एसएमई को सेवाएँ प्रदान करता है।

मेकमायट्रिप के सह-संस्थापक और ग्रुप सीईओ श्री राजेश मागो ने कहा मायबिज ने लगातार उन परिचालन चुनौतियों को हल करके उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाई है जो कंपनियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी के विस्तृत रेस्तरां नेटवर्क और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मायबिज के कॉरपोरेट ट्रैवल इकोसिस्टम से जोड़कर हम व्यावसायिक यात्रा के दौरान भोजन व्यय प्रबंधन की जटिलताओं को सरल बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य कॉरपोरेट यात्रा को कर्मचारियों और वित्त टीमों दोनों के लिए शुरू से अंत तक अधिक सहज और सुविधाजनक बनाना है।

स्विगी फूड मार्केटप्लेस के सीईओ श्री रोहित कपूर ने कहा व्यावसायिक यात्रा करने वाले जानते हैं कि कठिनाई अक्सर बैठक में नहीं बल्कि भोजन की व्यवस्था और उसके खर्च की रसीदों को संभालने में होती है। मायबिज के साथ यह साझेदारी इस परेशानी को दूर करती है। अब बिजनेस ट्रैवलर्स स्विगी के विशाल नेटवर्क से कहीं भी भोजन मंगवा सकते हैं या शहर में अपने पसंदीदा रेस्तरां में भोजन कर सकते हैं और भुगतान सीधे मायबिज वॉलेट से हो जाएगा। एक बार कॉरपोरेट आईडी से ऑथेंटिकेशन हो जाने पर पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य स्विगी ऑर्डर जैसी ही होती है चेकआउट से पहले बस कॉपोरेंट मोड चुनना होता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान है जो समय की बचत करता है झंझट कम करता है और व्यावसायिक यात्रा को और अधिक सुगम बनाता है।

उड़ान, होटल, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, वीजा और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी जटिल यात्रा श्रेणियों को सुव्यवस्थित करने के बाद, अब मायबिज और स्विगी मिलकर व्यवसायिक यात्राओं में भोजन खर्च, जो भारत के कॉरपोरेट यात्रा व्यय का 11 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस साझेदारी के तहत, कॉरपोरेट यात्री स्विगी ऐप पर 'स्विगी फॉर वर्क' के माध्यम से भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं और भुगतान सीधे मायबिज कॉरपोरेट वॉलेट से कर सकते हैं। यह सुविधा 720 से अधिक शहरों में 2.6 लाख से अधिक रेस्तरां पर डिलीवरी और 50 से ज्यादा शहरों में 40,000 से अधिक स्विगी डाइन आउट पार्टनर रेस्तरां में डाइन-आउट तक विस्तार पाती है। इस एकीकृत समाधान की मुख्य विशेषता है 'बिल टू कंपनी' फीचर, जो व्यक्तिगत भुगतान और रसीदों के प्रबंधन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। सभी लेन-देन स्वतः ही कंपनी के व्यय प्रबंधन सिस्टम में दर्ज हो जाते हैं, जिससे फाइनेंस टीम को वास्तविक समय में स्पष्ट दृश्यता मिलती है और कॉरपोरेट यात्रा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। कर्मचारियों के लिए इसका उपयोग करना भी बेहद सरल है कृ उन्हें केवल एक बार अपनी कॉरपोरेट आईडी से ऑथेंटिकेशन करना होता है, जिसके बाद वे तुरंत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 'स्विगी फॉर वर्क' के 'बिल कंपनी' फीचर के अलावा, उपयोगकताओं को स्विगी के कॉरपोरेट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के तहत फूड, डाइनआउट और इंस्टामार्ट सहित सभी यूनिट्स पर विशेष रिवॉर्ड्स और ऑफर्स मिलेंगे। यह प्रोग्राम मई में 30 से अधिक शहरों के 7,000 टेक पार्कों में लॉन्च किया गया था और इसे अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। केवल छह महीनों में, यह बढ़कर 27,000 से अधिक कॉरपोरेट्स और 2.5 लाख से अधिक प्रमाणित उपयोगकताओं तक पहुँच गया है।

व्यापारी के शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन

सलोंन रायबरेली । सलोंनं नगर के प्रसिद्ध व्यवसाई आत्मजीत सिंह द्वारा शहर रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर गुरु कृपा ऑटोमोबाइल्स की ब्रांच का शुभारंभ स्वयं द्वारा फीता काटकर किया। इस शोरूम में रॉयल एनफील्ड बुलेट एवं दो पहिया वाहनों की न्यू डीलरशिप की शुरूआत की । इस अवसर पर सरदार मंजीत सिंह , लकी अरोड़ा, परमजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी इरफान सिद्दीकी ,सुरेश गुप्ता चौधरी

की मुख्य महाप्रबंधक, सुश्री अपर्णा त्यागराजन; सेबी के मुख्य महाप्रबंधक, श्री राजेश आनंद गुज्जर; मुख्य व्यवसाय अधिकारी, श्री समीर पाटिल और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा डी डी पी कम्युनिटी

भारत टेक्स 2026 की घोषणा - भारत का वैश्विक टेक्सटाइल मेगा इवेंट जुलाई 2026 में वापसी करेगा

भारत टेक्स 2026 की घोषणा - वैश्विक टेक्सटाइल्स के अगले युग की ओर कदम

भारत का प्रमुख टेक्सटाइल मंच जुलाई 2026 में नवाचार, स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के साथ लौट रहा है

बीटीटीएफ ने जुलाई 2026 में होने वाले भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा की

` लखनऊ , 12 नवंबर 2025

भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन (BTTF) तीसरे संस्करण के आयोजन के लिए तैयार है। भारत टेक्स—देश का प्रमुख वैश्विक टेक्सटाइल और परिधान आयोजन है जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित होगा।

यह घोषणा आज भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन (BTTF) द्वारा की गई। BTTF अग्रणी निर्यात संवर्धन परिषदों (EPCs) और उद्योग संघों का एक प्रतिष्ठित संघ है। नेतृत्व ने आगामी संस्करण के विजन, पैमाने और प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हुए भारत टेक्स 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरूआत की।

भारत टेक्स के पहले दो संस्करणों ने इसे भारत के ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल्स इवेंट के रूप में स्थापित कर दिया है। दूसरा संस्करण, जो 14 से 17 फरवरी 2025 के बीच भारत मंडपम और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 2.2 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में आयोजित किया गया और अत्यंत सफल रहा। इस आयोजन में 5,000 से अधिक प्रदर्शक, 120+ देशों से 6,000 अंतरराष्ट्रीय खरीदार और 1,20,000 से अधिक दर्शक शामिल हुए। 80 से ज्यादा ज्ञान सत्रों, 8,000 से ज्यादा B2B/B2G बैठकों और उच्च स्तरीय नीति संवादों के साथ, इस संस्करण ने लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात अवसर और 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रतिबद्धताएं उत्पन्न कीं।

बीटीटीएफ के चेयरमैन श्री नरेन गोयनका ने कहा कि 2024 और 2025 के संस्करणों की शानदार सफलता के बाद, 2026 का संस्करण भारत की सम्पूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन के एकीकृत प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह संस्करण माननीय प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी 5F विजन—Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign—को और मजबूत करेगा तथा 'Reform, Perform, Transform and Inform' की शासन नीति के अनुरूप नवाचार, समावेशिता और स्थिरता पर केंद्रित भारत के टेक्सटाइल इकोसिस्टम की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। दुनिया के अग्रणी निमार्ता, खरीदार और उद्योग विशेषज्ञ एक ही मंच पर एकत्र होंगे, जहां विचार नेतृत्व सत्रों और अनुभवात्मक प्रदर्शनों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी।

बीटीटीएफ के सह-अध्यक्ष श्री भद्रेश डोढियो ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग 2026 होगा, जहां वैश्विक उद्योग नेता, साईओ, नीति निमार्ता और विशेषज्ञ I»»fdustry 4.0, ESG आवश्यकताओं, अनुसंधान, सहयोग और उभरते व्यापार परिदृश्यों पर विचार-विमर्श करेंगे।

श्री डोढियो ने आगे कहा कि भारत टेक्स 2026 भारत की प्रतिष्ठा को एक जिम्मेदार, स्थिर और विश्वसनीय वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में और मजबूत करेगा। यह MSMEs, स्टार्ट-अप्स और कारीगरों को वैश्विक बाजारों, निवेशकों और तकनीकी साझेदारों के साथ जुड़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। यह आयोजन भारत की सर्कुलर मैन्युफैक्चरिंग, जिम्मेदार उत्पादन और टेक्सटाइल नवाचार में नेतृत्व को उजागर करेगा, साथ ही डिजाइन लैब, इनोवेशन पवेलियनों और फैशन शोकेस के माध्यम से कौशल और रचनात्मकता का उत्सव मनाएगा।

भारत टेक्स 2026 सिर्फ टेक्सटाइल की ताकत दिखाने का मंच नहीं, बल्कि प्रगति की संभावनाओं को लोगों तक पहुंचाने की पहल है। जैसे ही दुनिया नई दिल्ली में एकत्र होगी, भारत अपनी सबसे प्रेरक टेक्सटाइल कहानी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

ऊर्जा मंत्री चला रहे आधुनिकता की ट्रेन, पर राजाजीपुरम में दौड़ी वसूली एक्सप्रेस

बिजली का तार नहीं, साहब की जेब का तार जोड़ो, तभी मिलेगी रोशनी!

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी जिस लगन से बिजली विभाग को आधुनिकता की ट्रेन पर सवार करने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को राजधानी के राजाजीपुरम चौराहे पर स्थित 33/11 के-वी सबस्टेशन के बाबू और इंजीनियर महोदय बड़े प्रेम से पटरी से उतार रहे हैं। जाहिर है, मंत्री जी की आधुनिकता यहाँ आकर बस वसूली के नए-नए ईजाद तरीकों तक ही सीमित रह गई है।

एक सीधे-साधे उपभोक्ता ने सोचा कि जब प्रदेश में बदलाव आ गया है, तो ईमानदारी का परचम लहराएगा। बेचारे ने नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उत्तर प्रदेश में ईमानदारी अभी भी एक निमार्णाधीन बिल्डिंग है!

काम शुरू हुआ सुपरवाइजर महेश्वर यादव से, जिन्होंने 10 दिन तक उपभोक्ता को विभाग में ही नचाया, फिर मामला अंशुमान पटेल को सौंप दिया। पटेल जी ने उपभोक्ता से बड़ी बेबाकी से कहा कि वह सिस्टम के बाहर से आए हैं। अगर सिस्टम शायद दलाल रूपी पुल से आते, तो अब तक काम हो जाता।

जब पत्रकार जो स्वयं उपभोक्ता भी थे, ने इस पर आपत्ति जताई, तो इंजीनियर अशोक की देखरेख में फॉर्म यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि मकान फिनिश होने के बावजूद बिजली के स्विच नहीं लगे हैं, मानो स्विच लगाना ही एकमात्र और सबसे बड़ा अपराध हो।

जिस उपभोक्ता को वायरिंग के बहाने कनेक्शन से वंचित किया गया, ठीक उसी क्षेत्र में अवैध बिल्डिंग कनेक्शन मिला, बड़ी सरलता से! सीलिंग का आदेश प्राप्त बिल्डिंग, कनेक्शन मिला, बड़ी तत्परता से! तीन शेड और बिना प्लास्टिक वाले मकान में कनेक्शन मिला, बिना किसी आपत्ति के! ऐसा लगता है कि बिजली विभाग के दफ्तर में अवैध निर्माण की फाइल पर तत्काल कार्रवाई की मुहर पहले से लगी होती है, जबकि साधारण उपभोक्ता की फाइल पर ठंडे बस्ते में डालो का ईमानदार आदेश होता है।

अधिकारियों की महानता देखिए। अभियंता अशोक इतने व्यस्त हैं कि उपभोक्ता का फोन उठाना उनके लिए विकास की राह में एक बड़ी बाधा बन जाता है।

इन महोदयों का व्यापार धमकी के दम पर खूब धड़ल्ले से चल रहा है। इनका सीधा संदेश है, अगर तुमने कहीं शिकायत की, तो हम तुम्हारे मीटर में ऐसी चीज लगा देंगे कि तुम्हें अपने जलाने से ज्यादा बिल जमा करना पड़ेगा।

यह कार्यशैली सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति का मजाक उड़ा रही है। ये किसी और को नहीं, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री को सीधे चूना लगा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार बिल्डरों से मोटी रकम लेकर धड़ल्ले से मीटर देने वाले और अपने वेतन से कई गुना ज्यादा संपत्ति बनाने वाले ये इंजीनियर मौज काट रहे हैं।

फिलहाल उपभोक्ता की मांग है कि इस वसूली एक्सप्रेस की जाँच विभाग नहीं, बल्कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय करे, ताकि इनकी अवैध संपत्तियों का हिसाब हो सके और यह पता चल सके कि वाकई इनकी पहुँच ऊपर तक है, या यह सब सिर्फ. धोखा है।

कलर्स के 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा' में नागिन 7 की नागरानी प्रियंका चाहर चौधरी बनीं 'पंगा-मेकर', ईशा और अभिषेक को कहा 'एक्स-फ्रेंड्स'!

इस वीकेंड कलर्स का शो 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा - जोडियों का रियलिटी चेक' लेकर आ रहा है एक ऐसा एपिसोड, जो चचाओं में रहने वाला है। टीवी की नई सर्प रानी और नागिन 7 की स्टार प्रियंका चाहर चौधरी अपने दिलकश अंदाज और शरारती मिजाज के साथ शो के सेट पर पहुंचती हैं। यह महज एक सेलिब्रिटी गेस्ट अपीयरेंस नहीं, बल्कि ट्विस्ट से भरा रीयूनियन है। प्रियंका, जिन्होंने कलर्स के लोकप्रिय शो उडारियां में कंटेस्टेंट्स ईशा मलवीया और अभिषेक कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की थी, इस बार लौटती हैं पूरी तैयारी के साथ — नुकीले डायलॉग्स और मस्ती भरी नोकझोंक के साथ। एपिसोड के दौरान वे लगातार ईशा और अभिषेक को अपने 'एक्स-फ्रेंड्स' कहती रहती हैं, जिससे दर्शक ठहाकों से गूंज उठते हैं और जोडियां पड़ जाती हैं कन्फ्यूजन में। लेकिन प्रियंका सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने नहीं आई हैं — वे लाई हैं अपने साथ एक कार्बन डाई ऑक्साइड गन! हर गलत जवाब पर वे कंटेस्टेंट्स पर ठंडी फुहार छोड़ती हैं, जिससे मंच बन जाता है एक मजेदार 'फ्रोजन वॉरजोन'।

एपिसोड का हाइलाइट है 'लेजेंडरी नागिन का ताज' एक्टिविटी, जहां प्रियंका जोड़ियों के बीच ऐसा हंगामा करती हैं कि सब हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं। जोड़ियां एक-दूसरे को देती हैं मजेदार खिताब — कौन है सबसे बोरिंग नाग, कौन है सबसे बातूनी नागिन — किसी पर भी कोई रोक नहीं! 'नाग मणि' टास्क में तो मजाकिया पागलपन अपने चरम पर पहुंच जाता है, और प्रियंका सच्ची सर्प रानी की तरह पूरे माहौल पर राज करती हैं। यह एक ऐसा फुल-सर्कल मोमेंट है जो टीवी पर कम ही देखने को मिलता है — उडारियां के को-स्टार्स अब नागिन 7 की रॉयल्टी के साथ एक मंच पर। प्रियंका लाती हैं पंगा, हंसी, और नागिन जैसी तीखी एनर्जी, जिससे सब सोच में पड़ जाते हैं — जब सर्प रानी सामने हो और उसके 'एक्स-फ्रेंड्स' हॉट सीट पर, तो अगला डंक किसे लगेगा? एक बात तो तय है — जब प्रियंका चाहर चौधरी मंच पर होती हैं, खेल बदल जाता है, और कोई भी उनके 'बाइट' से नहीं बच पाता!

निविया बॉडी मिल्क प्रस्तुत करता है 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा - जोडियों का रियलिटी चेक', को-पावर्ड बाय शुगर फ्री ग्रीन, कैडबरी डेयरी मिल्क, पोअर होम एयर फ्रेशनर्स, एन्वी परफ्यूम्स, लॉरियल पेरिस हायलूरॉन प्योर, और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। स्पेशल पार्टनर्सः कोलगेट और एचडीएफसी लाइफ। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे, सिर्फ कलर्स पर।